SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, we give it to the State Governments as per their quota. As far as taking up further monitoring is concerned, it is for the State Government to do it. Broadly, we look into the matter.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: महोदया, 3 साल पहले उस वक्त की सरकार ने एक प्रोग्राम किया था मॉडर्न बेकरीज़ के थ्रू, ताकि सस्ते दाम में गरीब लोगों को ब्रेड मिल जाए। उसके पब्लिक फंक्शंस दिल्ली और बंबई में किए गए थे और उन्होंने यह मूवमेंट प्राइवेट वेकरीज तक पहुंचाने की कोशिश कि थी। अब यह मालूम हो रहा है कि उस सरकार ने जो यह स्कीम गरीबों के लिए चालू की थी, एफ.सी.आई. उनको गेहूं नही दे रही है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। जो मैंन्युफैक्चरर्स ब्रेड बनाते हैं, उनको गेहूं नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको ब्लैक मार्केट से लेना पड़ता है, इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं और गरीबों को उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने कुछ डॉयरेक्शन दी है एफ.सी.आई. को कि गरीबों के लिए जो मैंयुफैक्चरर्स ब्रेड बनाते हैं, उनको प्रॉयोरिटी पर गेहूं दिया जाय? क्या इस दिशा में कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? हमारी जानकारी यह है कि उनको गेहूं नहीं मिल रहा है। तो गरीबों के लिए सरकार की जो यह स्कीम थी, उसके बारे में यदि आप प्रकाश डालें तो देश के गरीबों को कुछ फायदा हो जाएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I wonder which bakeries make bread for the *garib.*

गरीब को तो सूखी रोटी नहीं मिलती है।

SHRI SUSHILKJMAP SAMBHAJIRAO SHINDE: Madam, I would like to mention here that during the Prime Ministership of Shri, P.V. Narasimha Rao, out of two places in Delhi, I was present in one of the opening ceremonies in which bread was given at a very low price.

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैडम पाव तो खाते हैं बंबई में।

श्री चतुरानन मिश्र : एक तो उन्होंने एक खास कम्पनी मॉडर्न वेकरीज के बारे में कह, वह तो हम जांच करवा लेंगे तभी आपको कुछ बता सकते हैं कि ऐसा है या नहीं। अगर ब्रेड बनाते हैं तो यह लिखा नहीं रहेगा कि गरीब ही खाएं। जिसको खाना है खाए। हम तो गेहूं दे देंगे उनके नाम पर और वह ब्रेड बनएंगे।

श्री एन.के.पी. साल्वे : मंत्री महोदय की भाषा कुछ बदल रही है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : रईस की ब्रेड अलग होती है, छोटे लोगों की ब्रेड अलग होती है, पाव होती है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : पाव होता है बंबई में, गरीब से गरीब आदमी उसको खाता है।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कहा कि एक बार जब हम उनको गेहूं दे देगे तो गरीब खाए या अमीर खाए, यह तो उनके हाथ में रहेगा। हम देखेंगे कि अगर उनको गेहूं नहं मिलता है तो उसके लिए क्या किया जाए।

Establishment of Village/ Libraries

*482. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Department of culture had a proposal to begin from 1995-96 for setting up of Village Libraries with basic educational facilities; and

(b) if so, the reason as to why the proposal did not become a reality and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHIRAM SAIKIA): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal for School-cum-Village Library Scheme was not approved by Minsitry of Finance, which advised the evaluation of the existing schemes to avoid duplication.

An indepth evaluation of the schemes was undertaken and the scheme modified in the light of the 73rd and 74th Amendment of the Cratitution, whereby the Zila Parishad and the Panchayat Samities have been designated as the nodal agencies to offer Lbrary services at the rural level. Hence a scheme known as "the scheme of Financial Assistance for Setting up of Rural Libraries" has been

formulated and is propsoed to be implemented from the financial year 1997-98 through the Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta, which is the national agency for coordinating, developing and monitoring the library system in the country.

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा : उपसभापति महोदया, यह जो उत्तर दिया गया है उससे यह लगता है कि जो स्कूल कम विलेज लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट था, उसको विलेज लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट के रूप में बदल दिया गया है। दोनों दो चीजें थीं। खैर, विलेज लाइब्रेरी ही सही। मेरा इसमें प्रश्न यह है कि इस विलेज लाइब्रेरी की स्थापना के बारे में। एक शंका उत्पन्न होती है, जिसको मंत्री जी स्पष्ट करें। यहां शब्द है " ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना के लिए सहायता।" "ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना" नहीं "सहयता।" उपसभापति महोदया, मेरा यहां प्रश्न यह है कि इस ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना के बारे में भी जो एच.आर.डी. की स्टेडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया था कि इस साल तीन करोड़ के व्यय से यह योजना इस वर्ष में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के जरिए शुरू की जाएगी। मंत्री जी बताएं कि क्या तीन करोड़ इस साल में इस उद्देश्य के लिए खर्च किए जाने वाले हैं और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी को इसके लिए धन का आवंटन किया है?

SHRI MUHI RAM SAIKIA: Madam, the Department of Culture prepared a school-cum-library scheme. But, it was rejected by the Ministry of Finance on the ground that it may be a duplication of the existing libraries. It was also suggested by the Planning Commission that in view of the existing policy of the Government to transfer all the Centrally-sponsored schemes to the Stales, the scheme may be reconsidered. In the light of those considerations, a new scheme of . financial assistance for setting up rural libraries in rural areas to meet the reading needs of the village people, particularly in areas where there are no libraries or book shops was formulated. In the light of the 73rd and 74th Amendments of the Indian Constitution, Panchayat Samitis and Zila Parishads have been made the nodal agencies to support library services in the rural areas. This scheme has been prepared by the Department of Culture. Now it is waiting the approval of the Planning Commission. This scheme also provides Rs. 15 crores for the entire Plan period and Rs. 3 crores annually.

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा : उपसभापति महोदया, डा. रंगनाथ लाइब्रेरी मूवमेंट के बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति रह चुके हैं। यूनेस्को का 1941 का जो घोषणा पत्र है, डिक्लियरेशन है दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए अधिनियम होना जरूरी है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हमारे देश के सभी राज्यों ने इस अधिनियम के इस निर्देश को स्वीकार किया है और लाइब्रेरी अधिनियम हमारे सभी राज्यों में है? अगर नहीं है तो इसके लिए केन्द्र द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? मैडम, यह रेलेवेंट क्वेश्चन है इसलिए मंत्री जी ने बताया कि एक पंचायत राज एक्ट है इसके जरिए नोडल एजेन्सी का काम डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति करेगी लेकिन किस कानून के अन्दर करेगी? अगर बिहार में अधिनियम नहीं है, मध्य प्रदेश में अधिनियम नहीं है, अन्य राज्यों में अधिनियम नहीं है जहां पंचायत राज लागू हो गया है तो यह किसी अधिनियम के अन्तर्गत लागू होगा? क्या राज्य सरकारों के द्वारा अधिनियम बनाया जायेगा और जिन राज्यों ने अधिनियम नहीं बनाया है तो उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं? जिस यूनेस्को का हमारा देश सदस्य है और यूनेस्को के घोषणा पत्र को बहुत वर्ष हो गये हैं तो क्या आपने उसको स्वीकार किया है और इसके बारे में क्या उपाय किए गए हैं?

मैडम, मेरे प्रश्न का बी पार्ट यह है कि क्या पुस्तकालय मूवमेंट के लिए केन्द्र में एक अलग से विभाग की जरूरत आप महसूस करते हैं और क्या इसके लिए अलग से विभाग कायम किया जायेगा ? क्योंकि एक सलाहकार समिति ने अलग विभाग होने के बारे में विचार किया था और विभाग बनाने के बारे में सुझाव दिया था तो इसके बारे में आपका क्या उत्तर है ?

SHRI MUHI RAM SAIKIA: Madam, there are only eleven States where there is a legislation or an Act for libraries. Under this scheme, it is proposed to establish one village library in every Panchayati area where there is no village library existing. The scheme proposed to establish 200 village libraries during the year 1997-98. The scheme will provide financial assistance for construction of rural libraries in the Panchayati area. It also proposes to allot Rs. 1,50,000 for every library—Rs. 1,00,000 for

construction of a building and Rs. 50,000 for equipment and other infrastructure such as books journals, newspapers, etc. The State Government will have to udnertake the responsibility for recurring expenditure, maintenance of the library, maintenance of staff of the library and so on and so forth.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : उपसभापति महोदय, धन्यवाद । श्री नगेन्द्र नाथ ओझा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और हमें उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद पंडित नेहरू मौलाना आजाद और उनके सहयोगी रहे डा.राधा कृष्णनन ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे इस देश में उच्च शिक्षा का विकास हो और शिक्षा गांव गांव तक पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट भी शुरू किया । उपसभापति महोदय, आप जानती हैं कि इसी वजह से नेशनल बुक ट्रस्ट और एकडेमियां इत्यादि स्थापित हुई । इसी की कडी में राजा राम मोहन राय फाउण्डेशन है । आज हालत यह है कि हम अलग-अलग स्कीमों के नाम रखते हैं,नाम बदलते हैं और जो थोडी बहुत स्कूलों में लाइब्रेरियां हुआ करती थीं वे नष्ट हो गई हैं । उस संबंध में मैं कहना नहीं चाहता हूं । आज से 45-50 वर्ष पहले मैं जिस गांव में पढ़ता था उसको आप आज देखे तो आपको काफी फर्क मिलेगा और मैं समझता हूं कि यह सभी का अनुभव है ।

अतः मेरे प्रश्न का "अ" भाग यह है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आप नई-नई स्कीमें क्यों तैयार कर रहे है ? क्या आपने लाइब्रेरी पालिसी तैयार की है या नहीं ? जैसा कि आपने एक वर्ष पहले कहा था कि उसके अनेक अंग है और उन अंगों में गांव की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा है । शिक्षा के विकास के लिए महाराष्ट्र, केरला और काफी हद तक पश्चिमी बंगाल ने जो काम अच्छा किया है तो क्यों नहीं और इलाकों में वैसा काम हो रहा है । आज से 80 वर्ष पहले बडौदा में भी जब विलेज लाइब्रेरी फैली हुई थीं तो आज आप विलेज लाइब्रेरी का देश में विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे है ?

राजा राम मोहम राय फाउन्डेशन के संबंध में मैं अपना एक पुराना अनुभव बताना चाहता हूं । मेरा वहां कोई आलोचना करने का इरादा नहीं है । वह अनुभव यह है कि वहां किताबें बोरों में भरकर भेज दी जाती हैं, कौन उनको खोलता है, कहां वे लगाई जाती हैं, किसी को पता नहीं है । अब कठिनाई इस बात की है । इसी वजह से जैसा मैंने कहा मेरे प्रश्न का "अ" भाग है कि क्या आपने अपनी लाइब्रेरी पालिसी पूर्ण रूप से तैयार कर ली है और उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या किया है ? राज्य सरकारों से आपने क्या सहयोग लिया है क्या उनको समर्थन करते है और किसी प्रकार से आप अन्वेषण,मानिटरिंग करते है । ये स्कीमें गांव में पहुंचे और वास्तव में महिलाओं को उनका लाभ मिले ।

मेरे प्रश्न का "ब"भाग महोदय, यह है कि विलेज लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी दोनों को मिला दिया जाये । हमने जो कांस्टीट्शनल अमेंडमेंट पास किए हैं,बेचारे गांव वालें,शहर वाले और लोग हैं जो म्युनिसिपल बाडीज इत्यादि हैं,उनके ऊपर हम अपनी जिम्मेदारी थोप रहे है । न स्कूलों में लाइब्रेरी खुल रही हैं और न गांव के लिए किसी तरह उपलब्ध है । जब आप नीति तैयार करते हैं तो आपकी संयुक्त जिम्मेदारी है । आप कहते हैं कि फाइनेन्स मिनिस्ट्री के प्लान में है, उससे काम नहीं चलता है । किताबों की कीमतें बढ़ रहीं हैं । दर चाहे अधिक रेलवे के हों, पोस्टल रेट्स हों, कैसे महिलाएं मैगजीन्स मांगा सकती हैं,किताबे मंगा सकती हैं ?

श्रीमती कमला सिन्हा : ये सवाल हो रहा है या स्पैशल मैन्शन्ड ?

उपसभापति : सजेशन है । जवाब देने दीजिये ।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : महोदय, मैं शिक्षा सचिव भी रहा हूं । वे मेरे मंत्री थे इस वजह से मैं इसमें अधिक नहीं जाना चाहता हूं । एक तो वह मंत्रालय ऐसा है कि उसमें कभी-कभी कोई जाना-पहचाना जाना चाहता है तो उसको रखा नहीं जाता है । इसी से मैं उसके संबंध में कहना चाहता हूं ।...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : उनको बोलने दीजिये ।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मेरी बहन क्षमा करें । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इन विषयों पर वे क्या विचार कर रहे हैं । आप अपनी एक सर्वागीण पॉलिसी बनायें और देखें वास्तव में वे गांव में पहुंचे । पहले जो किताब नेशनल बुक ट्रस्ट दो रुपये में देता था,उसकी कीमत अब 25 रुपये है । आप कहेंगे कि उसकी भी कीमत और किसी वजह से बढाई जा रही है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको गम्भीरता से देखे और गम्भीरता से इस प्रश्न को आप लें । यह बिल्कुल ही एक नेग्लेक्टिड विषय है । वैसे यह सदन हमेशा इस बात की शिकायत करता है कि कम्पलसरी एज्युकेशन नहीं है, कोई पढ़ने की चीजें नहीं हैं और उसके बाद ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट कहते हैं नेशनल बिल्डिंग वर्क कहते हैं, उस समय हम यह कहते

हैं कि यह फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने यह नहीं किया या अगर कोई अधिक प्रश्न करता है तो कहते है कि ये अधिक समय ले रहा है।

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SHRI S. R. BOMMAI: There is a national Policy on Library which was accepted in 1989 wherein it has been laid down that libraries are to be established in rural areas also. As a result of this Constitutional Amendment, certain duties are allotcd to the village Panchayats as well as the district Panchayats. School and library maintenance would go to the zila Panchayats and the rural Panchayats. We have decided in the Chief Ministers' Conference that most of these subjects should be transferred to the States. The Central Government is going to assist them. It would be the responsibility of the State Government, the district Panchayats, and the village Panchayats. It is because it is part of their duties. Earlier, the library was there in the school itself. The school teacher used to take care of it. It was a part-time library. Later on, village Panchayats came and they are managing'it now. The Chairman of the Village Panchayat and the BDO are the members. The State Government also nominates members. That is how the new scheme is being implemented.

We are serious about it. We are impressing it upon the State Governments that they should take advantage of the assistance being given by the Central Government and that they should also contribute. Wherever the libraries are established, the funding is in the ratio of 3:1. The Central Government meets 75 per cent of the expenditure incurred in the establishment of the library.

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी केवल एक प्रश्न के तीन भाग पूछना चाहूंगी। पहला यह कि जब इस सदी की शुरूआत में साक्षरता का गांव-गांव तक प्रसार करने के लिए पुस्तकालय और पुस्तकालय कर्मियों कि भूमिका को रेखांकित कर लिया गया था तो जब हम इस सदी को समाप्त करने जा रहे हैं, आज़ादी की 50वीं वर्ष गांठ मनाने जा रहे हैं तो मेरे प्रश्न का भाग(ए) यह है कि क्या साक्षरता आन्दोलन अभियान से पुस्तकालय आन्दोलन को भी जोड़ा गया है? भाग (बी) में पूछना चाहती हूं कि पोस्ट लिटरेसी के लिए जो किताबें लिखी जा रही हैं क्या ग्रामीण स्तर पर जो पुस्तकालय हैं उनमें उन पुस्तकों को भेजा जा रहा है? मेरे प्रश्न का पार्ट (सी) यह है कि क्या मंत्री जी लाइब्रेरी नीति तय करने के लिए किसी अलग विभाग की बात सोच रहे हैं जैसे कि एच.आर.डी. की सलाहकार समिति ने 1996 में सुझाव दिया था?

SHRI S.R. BOMMAI: So far as the adult education programme is concerned, there will be co-ordination between the library movement and the Adult Education Department and the people who are involved in the field of education. The Government is trying to co-ordinate between all these agencies and see that neo-literates get the benefit of it.

SHRI BRATIN SENGUPTA: Madam, there are a number of educationally backward tribal-concentrated districts in our country. There are 41 identified educationally backward minority-concentrated districts. Due to the continuous rise in the price of newsprint, there has been an exorbitant increase in the price of vernacular textbooks. I would like to know whether these rural libraries would make adequate provision for appropriate vernacular textbooks for the targeted sections.

SHRI S. R. BOMMAI: We will make it.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, the hon. Minister has very ably explained the devolution of powers to the Panchayati Raj institutions. We have now passed on the buck to the State Governments and the State Governments, in turn, have passed it on to the Panchayats. But, if what Mr. Chaturvedi said is correct, it is not only a case of gross mismanagement, but there also happens to be no record whatsoever of the books and all that which are supposed to be kept in these libraries.

Now, it is a very commendable idea. He mentioned the names of great leaders who sponsored this idea to inculcate a sense of learning through libraries in the villages. It is a tremendous idea, Madam. Here, I have only one question to the hon. Minister; a very specific question. Is it not possible to have the system computerised? You are funding them. You are giving them money. But we just do not know where all this money that you are giving going into. He mentioned that the books are packed in sacks. It is a very indecent way of treating books. Is it not possible to put the whole thing in a computer at a central point? What is the difficulty in computerising it somewhere at a central point, even if these libraries are in the remotest villages, so that you are able to maintain a proper account?

SHRI S. R. BOMMAI: It is a very good suggestion. The Government would consider it.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपकी स्कीम है, तीन भाग आप देंगे और एक भाग स्टेट देगी । इसका जहां-जहां भी आपने प्रयोग किया है, उसका हमेशा नुकशान हुआ है । या तो कोई एक स्टेट बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल कर लेती है बाकी स्टेट्स बच जाती हैं। आप यह क्यों नहीं करते कि सभी स्टेट्स में इक्विटेबुल बेसिक पर इसको दे दें और पूरा खर्च अगर उठाएं तो सभी स्टेट्स में कुछ न कुछ लाइब्रेरियां खुल जाएंगी । नहीं तो जिन स्टेट्स में पैसा खर्च नहीं करते हैं, या नही है वहां एक लाइब्रेरी नहीं खुलेगी और बाकी जगह यह स्थिति होती है । दूसरा यह था कि क्या मेम्बर पार्लियामेंट का जो अपना वजट है उसमें अगर मैं कहीं लायब्रेरी खोलना चाहूं तो मुझे कहा जाता है कि आप बिल्डिंग तो बना दो, किताब नहीं खरीद सकते। किताब नहीं होगी तो बिल्डिंग खडी होकर क्या करेगी और बिल्डिंग खडी करते हैं तो किताबें वहां नहीं दे सकते और...

श्री एन. के. पी. साल्वे : किताब खरीदो तो बिल्डिंग नहीं बनाते ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उसी तरह से आप कंप्यूटर खरीदने की तो इजाजत देते हैं किताब खरीदने की इजाजत नहीं देते। अगर कंप्यूटर खरीदे जा सकते हैं स्कूलों के लिए तो किताबें खरीदने या स्पोर्टस का सामान खरीदने के ऊपर बैंअ क्यों लगा रखा है । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आपके सरकार के अपने पब्लिकेशंस हैं लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं जिनका किराया देने में आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं – जब हम उनसे पूछते हैं कि आप इन किताबों को डिसपोज आफ क्यों नहीं करते तो वे कहते हैं कि कोई रूल नहीं है तो आप उनको सारी लायब्रेरियों मैं या जो यहां दिल्ली में लाखों किताबें रखी हैं उनको दे सकते हैं **...(व्यवधान)...**

उपसभापति : मल्होत्रा जी, आपका पांचवां सप्लीमेंट्री है। प्लीज बी ब्रिफ ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बस उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यही पूछ रहा हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: 1 know, everybody is making big speeches, but please put your question.

SHRI S. R. BOMMAI As far as possible, there will be equitable help given to all the Slates. Hut I must also say that where the rural leadership is diligent, efficient and committed, there institutions grow well. I can give the instances of Maharashtra, Kerala and Karnataka. Sonic of the States are doing very well because of good rut al leadership. Where the rural leadership is not committed, these mistakes occur. Even in the libraries books arc not there, I do agree .... *(Interrputions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Too many questions have been asked.

SHRI S. R. BOMMAI: They have to be rectified. We will try to do it. *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Jichkar. *...(Interruptions)...* 1 already have three in line. *...(Interruption)...*

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Madam, we are now going into the 21st century. Now, for libraries in the village there is a limit. If they give Rs. 5 lakhs for a library in a village, they cannot purchase more than 5,000 books. This is the limit. Hon. Mr. Salve has cited, for example, the scheme of computers. The hon. Minister's Department already has a scheme called "Computers in Education." Now there is

another thing known as "Very Small Aperture Terminal" (VAST), which is connected to INSAT 2-B. This VSAT also costs Rs. 5 lakhs. The actual cost is less than a lakh of rupees, but because they take various commissions at various stages, the cost comes to Rs. 5 lakhs. So, if they provide a VSAT in every village, all the libraries in the world will be accessible to that village. Right from a first standard book to medicine and engineering books will be available free to a village. Such a great facility will be available free to a village. They already have a scheme called "Computers in Villages". Under our MPLADS we have done this in 12 schools in villages where we have show how, when a VSAT is installed in a village, the village comes into contact with the whole world through Internet. Will the Ministry take this up as a very broad based scheme?

SHRI S. R. BOMMAI: It is a very laudable suggestion. Government will definitely consider it seriously. But only one thing: Our hon. colleague, Salveji, has said that even books are missing from the libraries. We want to supply computers, but it depends upon the leadership of the village.

...*(Interruptions)*...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : जब यूरिया मिस हो जाता है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : चतुर्वेदी जी, बहुत सवाल हो गए हैं। जितने बुक्स नहीं उतने सवाल हो गए।

Not so many books arc there in the libraries in the villages. You have asked so many questions on it today. I know, everybody wants to ask about it.

... (*Interruptions*)...

श्री नरेश यादव : महोदया, देश में आधारभूत शिक्षा के विकास के लिए आजादी के बाद पूरे देश में पुस्तकालयों का गठन किया गया था। सरकार की तरफ से ध्यान न देने के कारण आज लगभग पूरे देश और खास करके गांवों के पुस्तकालय बंद हो गए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन सही ध्यान नहीं देनें के कारण से आज लगभग सभी पुस्तकालय बंद हो चुके हैं। हम यह चाहेंगे माननीय मंत्री जि से कि बिना फीस के उन गांवों के पुस्तकालयों का फिर से रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया जाय और दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि इस देश में एन.जी.ओज़ काफि अछा काम कर रहे हैं तो पुस्तकालयों के विकास में भी क्या एन.जी. ओज़ की सहभागिता ली जाएगी?

SHRI S. R. BOMMAI: Definitely, we will take co-operation from NGOs, wherever they are coming forward.

DR. KARAN SINGH: Madm, the House is aware that with the tremendous technological changes that are taking place, the very concept of the library has now changed. It is well known that a picture is equal to a thousand words. A video film is now equal to a thousand pictures. Therefore, when we open libraries, particularly in rural areas, is any attention being given to the possibility of having video access so that educational and other films, for example, those connected with health, sanitation, family planning and other matters with which villagers are directly involved, can be shown to them? Agricultural information can be given in a much more effective manner than simply in the old-fashioned way of distributing books.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a good suggestion.

SHRI S. R. BOMMAI: I do agree, Madam, the technological development has brought a revolution in the channel of information. Already the Indira Gandhi Open University has started making use of satellites and from one centre we are teaching a number of teachers in different towns in different States. We have started it, and we want to expand it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dave. I think all your questions have been asked and answers.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : महोदया, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। आज भी देश के कई गांवों में, छोटे –छोटे गांवों में, जहां गांवों के महजन होते हैं वे अपनी लाइब्रेरी रन कर रहे हैं। कई गांवों में छोटे-छोटे मित्र मंडल हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जो उन्होने एन.जी.ओज

का कहा, तो मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि इन सब की हेल्प ले कर के आप गांवों में लाइब्रेरी चलाएं? क्या सरकार यह योजना चाहती है या नहीं?

SHRI S. R. BOMMAI: The Government will take the help of any NGO or even village panchayats or anybody else, whoever comes forward.

THE DEPUTY GFfAIRMAN: Question No. 483.

SHRI SOM PAL Madam, I have a suggestion to make. Question NO. 483 and Question No. 484 may be combined together because they relate to the same subject.

THE DEPUTY CHAIRMAN: A decision was taken when the first question was taken up, when you were not present in the House. Even Question Nos. 481, 483, 484, 491 and 496 are all related questions. They were to be taken up together, but Mr. Gurudas Das gupta and others were not present at that time.

Low Procurement of Wheat and Steps to. Ensure Enough Supply for PDS

*483. SHRI GURUDAS DAS GUPTA†:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the procurement of wheat has been very low during the current procurement season as the farmers refused to take grains to mandis demanding hike in the minimum support price;

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto; and

(c) the steps proposed to ensure that the central pool has enough supplies for the Public Distribution System?

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) A statement is being placed on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) A total of 38.27 lakh tonnes of wheat has been procured during the current Rabi Marketing Season (1997-98) as on 8.5.1997, as against 64.94 lakh tonnes of wheat procured during the corresponding period of the previous season. Due to unseasonal rains and extended winter season, the harvest of wheat, this year, was delayed by some time. Agitation by a section of the farmers led by the Bhartiya Kisan Union demanding higher Minimum Support Price for wheat also affected the arrival of wheat in the mandies to some extent.

The Government of Punjab and Haryana had also requested for increase in the Minimum Support Price by at least Rs. 100/- per quintal and Rs. 135/- per quintal, respectively, in view of the high prices of wheat prevailing in the market. State Governments of other wheat procuring States had also expressed the view that increase in Minimum Support Price or payment of some bonus are necessary to ensure adequate level of procurement. Taking into account the view of the State Governments, the Central Government announced a bonus of Rs. 60/- per quintal, in addition to the Minimum Support Price of Rs. 415/- per quintal, for wheat procured for Central Pool during the period 17.3.1997 to 10.6.1997.

(c) The procurement price of wheat in 1997-98 season has gone up by Rs. 95/-per quintal (inclusive of bonus) which is 25% more than the price paid in the previous season. The Government has also decided to continue the ban on the export of wheat and wheat products over 1997-98 season and retain licensing and